target for saving of 5000 MW cf installed capacity has been envisaged for electricity sector and 6 million tonnes of petroleum products in the terminal year of the Eighth Plan (199€-97).

(e) The energy conservation measures proposed to be taken up in the Eighth Plan are given in the Eighth Plan Document Vol. IT Chapter on Energy (page 202 to 206).

विभिन्न राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वर्ग के प्रतिशत में विभिन्नता

2465. डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

श्री वीरेन जे. शाह :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वर्ग का प्रतिशत भिन्न-भिन्न है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वर्ग का प्रतिशत उस राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में कितना-कितना है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में गरीबी के राष्ट्रीय स्तर से अधिक गरीबी वाले राज्यों में गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित कार्यक्रमों को प्राथमिकता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांग) : (क) और (ख) जी, हां । वर्ष 1987-88 नवीनतम वर्ष जिसके लिए पूर्व में जारी किए गए गरीबी रेखा के नीचे रह रहे गरीबों का राज्यवार प्रतिशत उपलब्ध है, विवरण-1 में दिया गया है (नीचे देखिये)

1. योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने गरीबों के आकलन के लिए एक वैकल्पिक कार्यविधि की सिफारिश की है । विशेषज्ञ दल द्वारा गरीबों का राज्यवार और अखिल भारतीय अनुमान विवरण-2 में दिया गया है नीचे देखिये)

(ग) और (घ) जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के दो मुख्य कार्यक्रमों नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी. पी) और जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) का संबंध है, केन्द्रीय सहायता का आवंटन देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में विभिन्न राज्यों में ग्रामीण गरीबों के समानुपात के आधार पर किया जाता है । इसके अलावा, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, ऐसे 120 जिलों की पहचान की गई है जहां पर गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं बहुत विकट हैं और जहां सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिएं,

सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरुभूमियों, जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित 257 जिलों के 1752 पिछड़े ब्लाकों, जहां वर्तमान में सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालन में हैं, में 2-10-93 में रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण—I

1987–88 के लिये राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत

(अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	31.70
2.	असम	22.80
3.	बिहार	40.80
4.	गुजरात	18.40
5.	हरियाणा	11.60
6.	हिमाचल प्रदेश	9.20
7.	जम्मू व कश्मीर	13.90
8.	कर्नाटक	32.10
9.	केरल	17.70
10.	मध्य प्रदेश	36.70
11.	महाराष्ट्र	29.20
12.	उड़ीसा	44.70
13.	पंजाब	7.20
14.	राजस्थान	24.40
15.	तमिलनाडु	32.80
16.	उत्तर प्रदेश	35.10
17.	पश्चिम बंगाल	27.60
18.	छोटे राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	7.7(
19.	अखिल भारत	29.90

विवरण—2

गरीबों के समानुपात और संख्या पर विशेषज्ञ दल के अनुसार 1987–88 में गरीबों का राज्यवार प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	27.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	37.47
3.	असम	36.84
4.	बिहार	53.37
5.	गोवा	23.42
6.	गुजरात	32.33
7.	हरियाणा	16.63
8.	हिमाचल प्रदेश	15.46
9.	जम्मू व कश्मीर	23.20
10.	कर्नाटक	38.14
11.	केरल	32.08
12.	मध्य प्रदेश	43.40
13.	महाराष्ट्र	40.10
14.	मणिपुर	32.93
15.	मेघालय	34.60
16.	मिजोरम	32.52
17.	नागालैंड	34.85
18.	उड़ीसा	55.61
19.	पंजाब	12.70
20.	राजस्थान	34.60
21.	सिक्किम	34.67
22.	तमिलनाडु	45.13
23.	त्रिपुरा	36.84
24.	उत्तर प्रदेश	41.99
25.	पश्चिम बंगाल	43.99
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	दिल्ली	16.04
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	45.24
28.	चंडीगढ़	12.91
29.	दादर व नगर हवेली	18.71
30.	लक्षद्वीप	37.26
31.	पांडिचेरी	44.68
	अखिल भारत	39.34